



पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की 20 बड़ी उपलब्धियां ये रही

ब्रह्मोस डील, सबांग पोर्ट और IIM कैम्पस...

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जकार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक साबित हुई है। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो के साथ एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी द्विपक्षीय सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए करीब एक दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा, दवाएं और समुद्री सुरक्षा

जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि साल 2018 में हमने जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाई थी वह आज एक नई उड़ान भर रही है। हम विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि आज से भारत-इंडोनेशिया साझेदारी का एक स्वर्ण अध्याय शुरू हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साझा किए गए आधिकारिक विवरण और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा के दौरान कई बड़े और रणनीतिक ऐलान किए गए हैं।



सबांग पोर्ट का संयुक्त विकास: दोनों देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमत हुए हैं। ये स्ट्रेट ऑफ मक्का के ठीक सामने स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील की दूरी पर है।
UPI और डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन: भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब इंडोनेशिया के भुगतान सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा दोनों को बढ़ा बढ़ावा मिलेगा।
ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार: दोनों पक्षों ने ब्लू इकोनॉमी, समुद्री व्यापार और बंदरगाह विकास के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया है।
वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा: दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की, जहां पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के पुराने रुख को दोहराते हुए ट्विस्ट सॉल्यूशन और दीर्घकालिक शांति का समर्थन किया।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- » मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- » सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- » असाध्य घाव/शुगर के घाव
- » कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- » अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- » डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133
डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.
नेशनल हायपरबैरिक Dept. of Hyperbaric
रिसर्च सेंटर Fortis Escorts
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर
E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

भारत 8-9 को कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net
नई दिल्ली। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत, भारत 8 से 9 जुलाई, 2026 को केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सहयोग को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और समावेशी, सतत और दीर्घकालिक विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक में शामिल होंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता चार स्तंभों पर आधारित है, अनुकूलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ब्रिक्स महिला नेतृत्व वाले विकास को इन सभी आयामों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संरचित किया गया है। मंत्रिस्तरीय बैठक 6-7 जुलाई 2026 को आयोजित ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक के बाद हो रही है।

कहीं आप गलत तेल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं ?

देखी दिल के लिये, दादी वाला देखी तेल...

Kabira[®]

Healthy Growth
Yellow Mustard Oil

स्वदेशी पीली सरसों का तेल है, प्राचीन, पौष्टिक एवं परखा !

- ▶ प्राचीन शीतल विधि घागी से निर्मित।
- ▶ निर्माण विधि उच्च ताप रहित।
- ▶ निर्माण में कोई रासायनिक प्रयोग नहीं।
- ▶ कैंसर को रोकने में लाभदायक !*
- ▶ मधुमेह को नियंत्रित करने में लाभदायक।
- ▶ एसीडीटी एवं गैस्ट्रिक रोगों में मददगार।
- ▶ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक।
- ▶ केवल देसी सरसों द्वारा निर्मित।
- ▶ मांदाया घटाने में लाभदायक।
- ▶ बालों के लिए एक उत्तम तेल।
- ▶ ओमेगा 3 एवं ओमेगा 6 से भरपूर।
- ▶ लीची गंध रहित होने का कारण सभी ब्यंजनों में उपयुगी।
- ▶ अनेक औषधीय गुणों से भरपूर।
- ▶ सभी तेलों के मुकाबले सबसे कम सेच्युरेटेड फैट्स !*
- ▶ छः हजार वर्षों से मानव के लिए उपयोगी।

Kabira Cold Pressed Oils are Also Available in :
Kachchi Ghani Mustard Oil (Pungent Smell)
Kachchi Ghani Groundnut Oil | Kachchi Ghani Sesame (Til) Oil

स्वस्थ जीवन के लिए कौनसा तेल उपयोग करें ?

तेल आप उपयोग करें	तेल आप उपयोग ना करें
कबीरा पीली सरसों का तेल	कबीरा रिफाईंड घमोलेन तेल
कबीरा कच्ची घानी सरसों का तेल	कबीरा रिफाईंड राईस ब्रान तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस घमोलेन का तेल	कबीरा क्लॉन्ड एच क्लॉन्ड तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस तिलके का तेल	कबीरा रिफाईंड घमोलेन तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस बादाम तेल	कबीरा रिफाईंड घमोलेन तेल

Awards & Achievements :-

To Open Kabira Hand Made Exclusive Store or Other Trade Inquiries Please Contact :
MANISHANKAR OILS PVT LTD
ALSO DEALS IN KISAN, PEELRA, TILAK, HANDMADE, MURARKA, BANSI, KABIRA COLD PRESSED (EDIBLE OIL, SPICES & TEA)
+91 98290 50738
www.manishankar oils.in

University of Engineering & Management

IEM - UEM Group | Jaipur

THE World University Rankings 2026 | INDIAN UNIVERSITY RATINGS | CS I-GAUGE PLATINUM & DIAMOND | PRESTIGE | IOH | CAMBRIDGE English Educational Partner | GU GLOBAL UNIVERSITY RANKINGS | UGC APPROVED | AICTE APPROVED | NAAC ACCREDITED | AIU MEMBER | UNIVERSITY OF ACCREDITATION

B.TECH | M.TECH

Computer Science & Engineering | Data Science | AIML
Cloud Computing & Visualization | Electrical Engineering
Electronics & Communication Engineering | Civil Engineering
Mechanical Engineering

BBA | MBA

Marketing | Finance | Human Resource | Technology Management
Operations & Supply Chain Management | Digital Marketing
Hospital & Healthcare Management

BPT | MPT

Cardiopulmonary | Orthopaedics | Neurology
Musculoskeletal | Pediatrics | Sports

BCA | MCA

Data Science | Artificial Intelligence & Machine Learning
Full Stack Development | Cyber Security & Cloud Computing
AI & ML (Industry Integrated)

PGDY PH.D

Post Graduate Diploma in Yoga | Doctor of Philosophy

Academic Partners

tos SAS | IBM | SAS IIDE | CAMBRIDGE

Foreign University Collaborations

UNIV | SHANGHAI CHINESE UNIVERSITY | BRUNNEN UNIVERSITY | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

More than 18000+ Certification

HARVARD | COURSERA | LINKEDIN | INFOSYS | CAMBRIDGE | IBM | ledX

Top Placements

SCHOLARSHIPS UPTO 100%*

Subham Gourisaria
Tata Consultancy Services (TCS)

Soumen Pal
Metacube Software Pvt. Ltd.

Esha Mishra
Walmart Global Tech India

Aman Sharma
Metacube Software Pvt. Ltd.

Avinash Kumar
Metacube Software Pvt. Ltd.

Sourabh Chhipa
Metacube Software Pvt. Ltd.

Priyanka Biswas
Capegemini

Harshit Keshari
Tata Consultancy Services (TCS)

Soumadri Kapat
Wipro

Diprotit Mondal
Tech Mahindra

Snehashish Bhakat
Hashedra Technologies by DELOITTE

Aakash Sahani
Ubny Technologies Pvt. Ltd.

Swarup Sarkar
Tata Consultancy Services (TCS)

Kingshuk Bairagi
Cape Electric

Pranjal Bhattacharjee
Polycab India Pvt. Ltd.

Jatin Kumawat
Metacube Software Pvt. Ltd.

Karan Kumawat
Tata Consultancy Services (TCS)

Shreyantak Das
Wipro

Aniruddha Mukherjee
TCS Digital

Sanchita Brahma
Tech Mahindra

Study Abroad Program for Meritorious Students | USA, CANADA, UK, AUSTRALIA & SINGAPORE

5 Industry Established Labs | Leading University for 6G Projects, Govt. of India

Institution of Happiness QS - I-GAUGE Global Rankings Platform | Prestigious Learning Institute of India 2025 | World University Rankings 2026

www.uem.edu.in

Campus: 'Gurukul', Udaipuria Mod, Sikar Road, 6 Kms. from Chomu, Jaipur - 303807 (Raj.)
City Office: 210-212, IInd Floor, Apex Tower, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur | M: 9887933330

9887313330, 9887433330
9887413330, 9887153330

जागरूक जनता
ऑन लाइन पढ़ने के लिए स्कैन करें



ई-पेपर व अन्य खबरें देखें
jagrukjanta.net

सरकार घरों पर फ्री लगाएगी सोलर रूफटॉप, 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भजन लाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे का विस्तार करते हुए बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सितंबर से नया यूटिलिटी लेड मॉडल लागू करने की तैयारी में है। इस मॉडल के तहत पहले चरण में करीब 3 लाख घरों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे।



बिजली बिल शून्य होगा

नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उनके घरों पर डिस्कॉम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम निःशुल्क स्थापित करेगा, इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों की बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करना है, जिससे उनका मासिक बिजली बिल शून्य या बेहद कम हो सके।

उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा निवेश

अब तक पीएम सूर्य घर योजना में उपभोक्ता को पहले अपने स्तर पर सोलर रूफटॉप लगवाना पड़ता था, और बाद में निर्धारित सब्सिडी मिलती थी, लेकिन नए यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल में यह जिम्मेदारी सीधे डिस्कॉम निभाएगा, यानी पात्र उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरुआती निवेश नहीं करना होगा, डिस्कॉम ही उपकरणों की खरीद, स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य तकनीकी प्रैरि याओं का प्रबंधन करेगा।

सोलर रूफटॉप लगाने की रफतार तेज होगी

सरकार का मानना है कि इस मॉडल से सोलर रूफटॉप लगाने की रफतार तेज होगी, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, इससे घरेलू बिजली बिल में कमी आने के साथ-साथ पारंपरिक बिजली पर निर्भरता भी घटेगी।

जागरूक खबरें
जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा की अनुशंसा पर 50 लाख राशि के विकास कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति

जयपुर @ जागरूक जनता। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 50 लाख राशि की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया की आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के गलता तीर्थ संरक्षण हेतु सिविल मरम्मत एवं संरक्षण कार्य के लिए 50 लाख राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य की याचनान्वयन पटवर्तन विभाग के माध्यम से आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यह स्वीकृति सांसद मंजू शर्मा की अनुशंसा पर जारी की गई है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के साथ ही निर्धारित नियमों एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण कर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इस कार्य के पूर्ण होने से गलता तीर्थ संरक्षण एवं आभारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के लिए तीन नए सह प्रभारियों नियुक्त

जयपुर @ जागरूक जनता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं श्री धीरज टोंकस जी ने राजस्थान में संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तीन नए सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार श्री महेश खोचो, डॉ. सत्यवान राणा एवं डॉ. नीतू मान को राजस्थान का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आप राजस्थान के प्रभारी धीरज टोंकस का प्रदेश संगठन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क में की बढ़ोतरी

अजमेर/जयपुर @ जागरूक जनता। बोर्ड परीक्षा पर महंगाई की मार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की है। करीब 8 साल बाद बोर्ड परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में करीब 33 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी देयना कर दिया गया है। बढ़ा हुआ शुल्क बोर्ड परीक्षा-2027 से लागू किया गया है। इससे बोर्ड को करीब 45 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आय होगी।

जयपुर में जमीन होगी महंगी

49 फीसदी तक बढ़ेंगे दाम, 7 दिन के भीतर ही लागू होगी नई डीएलसी रेट

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। जयपुर में जमीन खरीदना अब महंगा हो सकता है, शहर में जमीनें 49 फीसदी तक महंगी हो सकती हैं, जिसे 7 दिन के भीतर ही लागू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की बैठक में डीएलसी दरों में बड़े बदलाव का फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में डीएलसी दरों को लेकर रिवाइज करने का निर्णय लिया है, शहर की डीएलसी दरों में 10% से लेकर 49% तक की बढ़ोतरी की प्रस्तावित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल महीने में भी डीएलसी दरों में 10% की वृद्धि की गई थी। इस बार जिन क्षेत्रों में बाजार मूल्य अधिक है और जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहां दरों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं, कुछ इलाकों में डीएलसी दरें घटाने के प्रस्ताव भी सामने रखे गए हैं।

तय्यार होती है डीएलसी रेट

किसी भी जमीन की बाजार कीमत सरकार निर्धारित करती है, यही डीएलसी रेट होती है, जिसे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक में तय किया जाता है, डीएलसी की दरों पर जमीन की रजिस्ट्री या भूमि का आवंटन होता है, नगर निकाय द्वारा आरक्षित दर पर जमीन आवंटन के साथ ही विकास शुल्क को भी शामिल किया जाता है।

50 फीसदी से अधिक की दरों पर सरकार करेगी फैसला

जानकारी के मुताबिक, 50% से कम बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव 7 दिन के भीतर लागू कर दिए जाएंगे, जबकि 50% से अधिक वृद्धि वाले प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, इसी तरह, दरों में कमी से जुड़े प्रस्तावों पर भी अंतिम फैसला राज्य सरकार ही करेगी, नई डीएलसी दरों का सीधा असर संपत्ति की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री पर पड़ेगा।

डॉ. मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है-चतुर्वेदी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। शांति एवं अहिंसा निदेशालय, राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सभागार में "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: व्यक्तित्व एवं कृतित्व" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान तथा उनके विचारों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके आदर्श, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। विशिष्ट अतिथि विधायक बालमुकुन्दचर्या जी महाराज ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना का अद्वितीय उदाहरण है।



उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे उनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक बाबूलाल जी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और सांस्कृतिक चेतना का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके विचारों एवं आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के

कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान केवल आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय 'यै मूल्यों', सामाजिक उत्तरदायित्व और चरित्र निर्माण की भावना विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान से परिचित कराया गया, ताकि वे उनके

विचारों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। शांति एवं अहिंसा निदेशालय, राजस्थान सरकार के निदेशक अजय अस्वाल ने कहा कि ऐसे आयोजन महापुरुषों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सकारात्मक नागरिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देते हैं। संगोष्ठी के समन्वयक एवं संस्थान के उपनिदेशक चन्द्रशेखर शर्मा ने कार्यक्रम में पहले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मधु रघुवंशी, कुलसचिव प्रो. अनिता शर्मा, प्रो. पी. हेमंता, संयुक्त निदेशक जे.पी. शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर भी चर्चा की। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में संस्थान के शिक्षक, चिकित्सक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पिता की किडनी से जिण्डा 22 साल का बेटा, शुक्रवार को एसएमएस में होगा ट्रांसप्लांट

जयपुर @ जागरूक जनता। एसएमएस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अबसुचारु हो गई है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे मरीजों और परिवारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। इस नई शुरुआत की सबसे प्रेरक कहानी 22 वर्षीय आदित्य की है, वीडेक के आखिरी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे आदित्य के लिए तब दुनिया धम गई जब उनकी दोनों किडनी फेल हो गईं, पढ़ाई छोड़कर जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर आदित्य के लिए अब राहत की खबर है कि एसएमएस अस्पताल में उनका ट्रांसप्लांट होगा, इस मुश्किल घड़ी में उनके पिता ने अपनी किडनी देकर बेटे को जीवनदान देने का निर्णय लिया है। वहीं, मुंबई से आए 30 वर्षीय सोनू का ट्रांसप्लांट भी इसी शुक्रवार को तय है।

मोबाइल ऐप से ई-रिक्शा को लॉक करना पड़ेगा भारी, जयपुर पुलिस ने दी चेतावनी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। देश भर में ई रिक्शा को लॉक करने की एक अफवाह चल रही है, लेकिन पड़ताल की तो यह बात सच साबित हुई, जयपुर के DCP सायथ राजर्षि राज ने बताया कि 1 दो घटना ऐसी हुई है, हालांकि थाने तक किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया, उन्होंने बताया कि ये रिक्शा चाइनीस बैटरी से ऑपरेट होते हैं, उसका एक ऐप आता है और उस ऐप से है वह लॉक हो जाता है। इसका मकसद यह था कि कभी ई रिक्शा चोरी हो तो उसे लॉक किया जा सके, ताकि कोई चोर उसे इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन अब कुछ असामाजिक



तत्व इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ई रिक्शा में बैटरी होती है, उसका ब्लूटूथ रेंज आस पास के मोबाइल में पकड़ता है तो असामाजिक तत्व उस ब्लूटूथ रेंज में आकर अपने मोबाइल में उस चाइनीज ऐप से बैटरी को जोड़कर ई रिक्शा को लॉक कर रहे हैं, हालांकि उसे इसका आर्थिक फायदा तो नहीं हो रहा लेकिन वह है मस्ती मजाक में ऐसा कर रहे हैं। IPS राजर्षि राज का कहना है कि चालक पुलिस से संपर्क कर सकता है, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी हरकत नहीं करें वरना आपको पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है, ई रिक्शा चालक मेहनत करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाए।

एन. के. पब्लिक स्कूल में इन्टर-हाउस एकल नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। आर्य नगर, मुरलीपुरा स्थित एन. के. पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्टर-हाउस एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न नृत्य शैलियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।



केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। विद्यालय के निदेशक डॉ. एन. सी. लुनायच ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए

शिक्षा के साथ-साथ कला, संस्कृति एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों को समान महत्व देना है। प्रधानाचार्या चित्रा राजे बंसरा ने कहा कि प्रत्येक प्रतिभागी ने पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के सलाहकार वी. एन. त्रिवेदी, समन्वयक डॉ. नाहिर खान, प्रधानाध्यापिका माला शर्मा एवं समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे।

महानिदेशक पुलिस ने पेश किया राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड

गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी, पेपर लीक पर लगी रोक

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने विगत समय में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट, पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्रवाई, नशा तस्करो और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियान तथा नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन ने प्रदेश की पुलिसिंग को नई पहचान दी है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गत 6 महिनों की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि अब राजस्थान पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम, अपराधियों



की आर्थिक कमर तोड़ने और तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। डीजीपी शर्मा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस की सजगता और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग के चलते 2025 की प्रथम छमाही तथा 2026 की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज होने वाले कुल अपराधों में 4.65 प्रतिशत की उल्लेखनीय

गिरावट आई है। 2025 की समान अवधि में 99272 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2026 की इस अवधि में यह संख्या घटकर 94652 रह गई है। इसके विपरीत, पुलिस द्वारा की गई स्वतः स्फूर्त कार्रवाई के कारण स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि (49087 से बढ़कर 51172 केस) दर्ज हुई है, जो अपराधियों के खिलाफ पुलिस की आक्रामक रणनीति को प्रदर्शित करती है।

HAJRI Smart Attendance, Stronger Workforce

Track Smarter. Manage Better.

Field Staff Tracking & Attendance System

A complete solution to track your field staff in real-time and manage attendance with accuracy and transparency.

- Real-Time Location Tracking
- GPS Based Attendance
- Detailed Reports & Analytics
- Secure & Reliable System

Why Choose HAJRI?

- Increase Productivity
- Improve Accountability
- Reduce Manual Work
- Save Time & Cost
- 100% Data Transparency

Take Control of Your Field Workforce
[Book a Free Demo](http://www.hajri.in)

www.hajri.in

Visit Our Website: www.hajri.in | Call Us: +91 9785555586 | Email Us: info@hajri.in

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

प्रदेश में होंगे डॉ. मुखर्जी के नाम पर चार पार्कों के नाम



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रखर राष्ट्रवादी चितक एवं शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के चार प्रमुख पार्कों का नाम उनके नाम पर करने एवं उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर-12 योजना स्थित पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम

पर किया जाएगा। साथ ही, इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनके विचार, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। ऐसे में यह पहल भावी पीढ़ियों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरणा देने का एक विनम्र प्रयास है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे उनके आदर्शों और संकल्पों को आत्मसात करते हुए विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह : 'सहकार से समृद्धि' मंत्र के साथ देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास में आए क्रांतिकारी बदलाव

8 लाख 90 हजार नवीन सदस्यों के जुड़ने से प्रदेश में और मजबूत हुआ 'सहकार परिवार'-शर्मा

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

जयपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास करते हुए बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। 'सहकार से समृद्धि' की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु प्रदान की। जिससे देश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। रोडमैप बनाकर सहकारी क्षेत्र में मौजूद रिक्तता को भरने का काम किया गया। साथ ही, सहकारी व्यवस्था को तकनीक रूप से सक्षम एवं पारदर्शी बनाया गया। उन्होंने कहा कि पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) को तकनीक आधारित बनाने हुए ई-पैक्स विकसित किए गए हैं, जिसके जरिए कार्य एवं अंकेक्षण आसान हो गया है। वहीं, डिजिटल पैमेंट सिस्टम से भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता आई है।



केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता से ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों एवं महिलाओं को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा है। उन्होंने देश के किसानों से आर्गेनिक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। केमिकल और फर्टिलाइजर से उत्पादन बढ़ने की बजाय जमीन की उर्वरता को नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर नमन करते हुए कहा कि उन्हीं की राष्ट्रवादी सोच के कारण कश्मीर, असम और प. बंगाल आज भारत का हिस्सा हैं। उन्होंने देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 हटाकर उनका सपना पूरा किया है।

सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ सहकारिता देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बन गई है। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन राजस्थान के हर गांव-ढाणी तक पहुंच गया है। राज्य में लगभग 42 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे एक करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। वहीं, सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8 लाख 90 हजार नवीन सदस्य सहकारी समितियों में जोड़े गए हैं। साथ ही, सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का आधार बन चुका है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में घाटे में चल रहे डेयरी संघ मुनाफे में आ गए हैं।

राजस्थान को मिली सौगातें

- 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास
- 50 गोदामों का लोकार्पण
- 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण
- 'सहकार वन' का हुआ ई-भूमि पूजन
- जयपुर के सुमेल गांव में बनेगा 'सहकार वन'
- 64 एकड़ जमीन पर होगा विकसित यह वन
- खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे वृक्ष लगाए जाएंगे
- मियावाकी और सामान्य प्रणाली से होगा पौधारोपण

5 हजार 646 से ज्यादा बने ई-पैक्स, 10 करोड़ से अधिक हुए ऑनलाइन लेनदेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कम्प्यूटरीकरण अभियान को भी नई गति दी है। प्रथम चरण में 5 हजार 646 पैक्स को ई-पैक्स बनाया जा चुका है। इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजेक्शन का लगभग एक तिहाई है और देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश की लगभग 4 हजार 875 पैक्स तीन या उससे अधिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। इनके माध्यम से कोमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 5 हजार 279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1 हजार 977 एम-पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

रिफाइनरी उद्घाटन समारोह बना जनसहभागिता का उत्सव: वर्चुअल माध्यम से जुड़ कर स्थापित किया अनूठा कीर्तिमान

ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण के साक्षी बने 53 लाख से ज्यादा प्रदेशवासी

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सतत प्रयासों से राजस्थान रिफाइनरी उद्घाटन समारोह ने जनसहभागिता और डिजिटल कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित किये हैं। इस अवसर पर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला।



जो प्रदेश की प्रगति को नई दिशा प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक अवसर ने राजस्थान को विकास की नई उचाईयों की ओर अग्रसर करने के संकल्प को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में शनिवार को

बालोतरा के पंचपदरा में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण व्यापक स्तर पर सुनिश्चित किया गया। इस आयोजन को प्रदेशभर की 12 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला मुख्यालयों सहित समस्त नगर पालिका, नगर

परिषद एवं नगर निगम मुख्यालयों से जोड़ा गया। वर्चुअल माध्यम से जनप्रतिनिधियों, नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों सहित 53 लाख से अधिक प्रदेशवासियों ने जुड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ओजस्वी भाषण सुना एवं समारोह में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज करवाई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक वर्चुअल माध्यम से समारोह का प्रसारण करने के निर्देश दिये थे, जिसके परिणाम स्वरूप जन-जन का उत्सव बन सका।

मुख्यमंत्री ने ली मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक

टनल में सुरक्षा सहित सभी मानकों की पालना हो सुनिश्चित



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस-वे देश की अवसरचक्रात्मक विकास एवं आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण एवं रखरखाव डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 8 किलोमीटर से अधिक लंबी मुकुंदरा टनल में सुरक्षा सहित सभी तकनीकी एवं पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं यात्री सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने पर भी जोर

पांचना बांध के एक गेट में आई तकनीकी खराबी को दूर कर खोला गया

जयपुर @ जागरूक जनता। राजस्थान में करौली जिले के पांचना बांध से सोमवार को बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू करने के बाद एक गेट में आई तकनीकी खराबी को भी दूर कर मंगलवार तड़के उसे भी खोल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और लगातार निगरानी से पांचना बांध समझौते से जल प्रवाहित होने लगा है। सोमवार को इस बांध से पानी छोड़ना शुरू करने के दौरान करीब 20 साल से बंद एक गेट तकनीकी खामी के चलते नहीं खुल पाया लेकिन इसे खोलने के लिए रात भर दूर करने में राज्य आपदा मोचन बल एवं जल संसाधन विभाग की टीमें जुटी रही।

"मंत्री पद का दुरुपयोग किया", एसीबी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए महेश जोशी को नहीं दी जमानत

जयपुर @ जागरूक जनता। जेजेएम घोटाले में ACB कोर्ट ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बडया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जज राजेश दंडिया ने टिप्पणी की कि आरोपी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग कर अपराध किया, जो आमजन के विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है। ऐसे मामले में जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि महेश जोशी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए सह-आरोपियों के साथ मिलकर प्रभाव का उपयोग किया, और ऊंची दरों पर टेंडर जारी करवाए। ईंकरक कंपनी के फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। साथ ही, वित्त समिति और बीडीपी पर नियंत्रण होने के बावजूद ऐसे निर्णय लिए गए, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।

जल्द होंगे NSUI के संगठन चुनाव, 16 से 27 साल की आयु वाले लड़ सकेंगे चुनाव

जयपुर @ जागरूक जनता। यूथ कांग्रेस के बाद अब एनएसयूआई के भी जल्द संगठन चुनाव होंगे। पहले चरण में यूनियर्सिटी और कॉलेज में चुनाव होंगे उसके बाद मिला और स्टेट लेवल पर चुनाव कराए जाएंगे। खास बात है कि कैम्पस में अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले ही फिर जिला और स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ सकेंगे और वोट डालेंगे। आखिरकार कांग्रेस के अंतिम संगठन एनएसयूआई ने एक बार फिर आधिकारिक रूप से संगठन चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का भी गठन हो चुका है। एनएसयूआई ने संगठन चुनाव दो चरणों में कराने का फैसला किया है। संगठन का दावा है कि पूरा चुनाव पारदर्शी होगा और सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा।

जयपुर में ट्रेले ने रौंदी 4 जिंदगीयां, 1 गंभीर घायल, 200 फीट बाइपास पर हुआ हादसा

जयपुर @ जागरूक जनता। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 की मौत, 1 गंभीर घायल है। 200 फीट बाइपास पर हादसा हुआ था। हादसे में 1 ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। पिता और 3 बच्चों की मौत हुई है। मां का एरएमएर ट्रोमा में इलाज जारी है। एक हादसे में हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया। मृतकों की पहचान चंद्रकाश्या, उनके पुत्र रमेश उम्र 11 वर्ष, रतन उम्र 10 वर्ष, दीपक उम्र 8 वर्ष की मौत हुई।

जगद्गुरु श्री कृपालू जी महाराज के दिव्य प्रवचन एवं मधुर संकीर्तन निम्न TV चैनल्स पर अवश्य श्रवण करें

सुश्री श्रीधरी दीदी

NEWS 18 इंडिया: 5:30 AM EVERY DAY

न्यूज 24: 6:00 AM EVERY DAY

भारत समाचार: 6:50 AM EVERY DAY

सूचना: 8:15 AM EVERY DAY

संस्कार: 8:30 PM MON - SAT

You Tube JagadguruKripaluJIMaharaj

You Tube ShreedhariDidi

JETHI TECH SOLUTIONS

Follow Us: @jethitech

ADDING WINGS TO YOUR BUSINESS

BULK SMS - Lowest Price

Buy 1 Lakh SMS @ Rs.12000/- With Free Control Panel @ 12 Paisa Per SMS LIFETIME VALIDITY

START-UP PACKAGE

Dynamic Website + Domain & Hosting(1 Year) + Social Media Profile Creation + Social Media Management*(1 Year) + 3 WhatsApp Stickers + WhatsApp Chat Direct Link + Local Business Listing + Logo Design

All For Just Rs.35,000/- + GST

WEDDING INVITATION

1 Invitation Video for Whatsapp 10,000 Bulk SMS 1 Social HashTag Creation 1 Whatsapp Direct Chat Link 1 Landing Page Send Digital Invitations At One Click

Digital Branding/Marketing

★ Youtube Marketing ★ Website Development ★ Digital Marketing ★ Android Development ★ Whatsapp Marketing ★ Software Development ★ Bulk SMS Marketing ★ Social Media Management

Corporate Branding/Identity

★ Visiting Cards ★ ID Cards ★ Letterhead ★ Calendars ★ Pen Stand ★ Mugs ★ Pamphlets ★ Banners ★ Envelope ★ Diary ★ Paper Weights ★ T-Shirts ★ Bill Book ★ Brochure ★ Signages ★ Bags ★ Pen ★ Many More...

Financial Services: Business Loan, Home Loan, CC Limit, Mortgage Loan

WE ARE Google Partner, Marketing Partner, Accredited Professional, Bing ads

DIGITAL MARKETING | CORPORATE BRANDING | PRINT MEDIA WEBSITE DESIGN/DEVELOPMENT | SOFTWARE DEVELOPMENT ANDROID/iOS APPS | BULK SMS | CRM/ERP SOFTWARE

INIDIA: 1C, Rajputana Marg, Kalyanpuri, Jhotwara, Jaipur-12 USA: 11923 NE Summer St. Portland, Oregon, 97220, USA +91-7976625313, +1(503) 8788224 || www.jethitech.com || sales@jethitech.com

सम्पादकीय

सुस्त मानसून, खेती पर संकट!

मानसून की बेरुखी खेती पर संकट बनती नजर आ रही है। कमजोर मानसून से खरीफ फसलों की बोआई इस महीने भी पिछड़ रही है। इस सीजन की प्रमुख फसल धान से लेकर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, व कपास के रकबा में गिरावट दर्ज की गई है। जून महीने में बारिश में करीब 40 फीसदी कमी आई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 5 जुलाई तक 350.85 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई जा चुकी हैं, जो पिछली समान के रकबा 442.80 लाख हेक्टेयर से 20.76 फीसदी कम हैं। इस दौरान कपास का रकबा करीब 23 फीसदी घटकर 23.18 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि गन्ने का 1.52 फीसदी बढ़कर 57.58 लाख हेक्टेयर हो गया।



कृषि व किसान कल्याण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 5 जुलाई तक खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल धान का रकबा 60.24 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, पिछली समान अवधि में यह आंकड़ा 69.30 लाख हेक्टेयर था। इस तरह इस साल अब तक इसकी बोआई में करीब 13 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। इस सीजन में धान का सामान्य रकबा 412 लाख हेक्टेयर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस खरीफ सीजन में 5 जुलाई तक दलहन फसलों की बोआई 37.15 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछली समान अवधि की 47.49 लाख हेक्टेयर से 21.78 फीसदी कम रही। इस सीजन की सबसे बड़ी दलहन फसल अरहर का रकबा 41.19 फीसदी घटकर 12.35 लाख हेक्टेयर रह गया। इस दौरान मूंग का रकबा 2.27 फीसदी घटकर 16.81 लाख हेक्टेयर और उड़द का 35 फीसदी घटकर करीब 3 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 5 जुलाई तक 66.31 लाख हेक्टेयर में तिलहन फसलें बोई जा चुकी हैं, जो पिछली समान अवधि में बोई गई 109.27 लाख हेक्टेयर से 39.33 फीसदी कम हैं। इस सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन का रकबा 39.65 फीसदी घटकर 47.80 लाख हेक्टेयर रह गया, जबकि मूंगफली का 39.54 फीसदी घटकर 16.93 लाख हेक्टेयर रह गया।

चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाजों का रकबा भी पिछड़ रहा है। 5 जुलाई तक इन अनाजों का रकबा 60.12 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो पिछली समान अवधि के रकबा 71.86 लाख हेक्टेयर से 16.34 फीसदी कम है। इन अनाजों में बाजरा की बोआई 30.60 फीसदी घटकर 20.82 लाख हेक्टेयर और मूंगफली की 39.54 फीसदी घटकर 16.93 लाख हेक्टेयर रह गई।

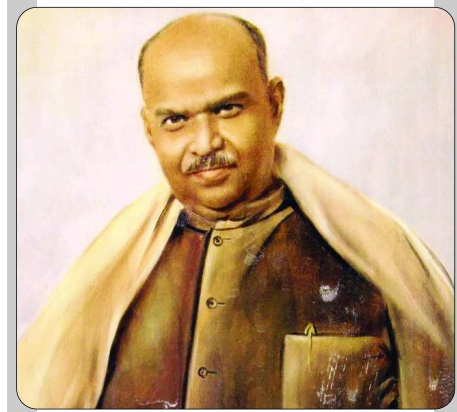
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिली

» जागरूक जनता | jagrukjanta.net

आज, छह जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है। आज हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। आधुनिक भारत के कुछ ही नेताओं में इतने सारे गुण एक साथ देखने को मिलते हैं।

श्यामा प्रसाद जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, जहां उन्हें सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन आसानी से मिल सकता था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी की गिनती अपने समय के महान शिक्षाविदों में होती थी। लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद श्यामा प्रसाद जी ने त्याग और राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ना ही या मानवीय संकटों का सामना, वे अपने समय की इन चुनौतियों के सामने मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया और बाद में पत्नी का भी निधन हो गया। लेकिन इन दुखद परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और आखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते से डिगा नहीं सकी। जब नजरबंदी के दौरान उनका निधन हुआ, तब वे उन अनगिनत लोगों से बहुत दूर थे, जिनके लिए वे जीवनभर संघर्ष करते रहे। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉ. मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही था। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि डॉ. मुखर्जी ने उस



उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया, जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। दशकों बाद, साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35(ए) को हटया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी।

डॉ. मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके लिए उन्होंने मजबूत संस्थानों का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं, जो उस समय की सोच से काफी आगे थीं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए, जो राष्ट्रहित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। डॉ. मुखर्जी के जीवन के बाद के वर्षों में इस भावना का एक और उदाहरण तब देखने को मिला, जब उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का निर्णय लिया। उस समय देश में हर तरफ कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि देश को एक ऐसे नए विकल्प की बहुत जरूरत है, जो भारत की प्रगति की बात भी करे और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का चुनाव चिह्न दीपक यानी मिट्टी का दीया रखा गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल बेहद अहम रहा। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जाता है, जिनकी दृष्टि विराट थी। उन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की। इसके माध्यम से आधुनिक

औद्योगिक भारत की नींव रखी। वे हथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हितों के भी प्रबल समर्थक थे।

यहां मैं अपना एक निजी अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट दृष्टि के साथ जिस सिंदरी संयंत्र की स्थापना के लिए डॉ. मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, उसकी कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार को उसके पुनरुद्धार का सीमाय मिली। उस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे सार्वजनिक जीवन के सबसे विशेष और अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया।

डॉ. मुखर्जी इस लोकतांत्रिक भावना के सशक्त प्रतीक थे। उन्होंने पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होना इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्र निर्माण का दायित्व राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है। उन्होंने पूरी निष्ठा और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ स्थानों पर देशहित में अलग मार्ग अपनाया आवश्यक है, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

75 वर्ष पहले पंडित नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना गया। तब डॉ. मुखर्जी इसके सबसे मुखर आलोचक रहे थे। वे भली-भांति समझ चुके थे कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। समय के साथ उनकी यह आशंका सही साबित हुई। जो पार्टी 75 वर्ष पहले पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी, उसी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा।

वर्ष 1943 में जब बंगाल भीषण अकाल की त्रासदी से जूझ रहा था, तब उन्होंने पीड़ितों की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को भोजन मिल सके, जिसके लिए कई कैटिन और राहत केंद्र शुरू किए गए। कोलकाता के एक कॉलेज में युवाओं को संबोधित करते हुए डॉ. मुखर्जी ने उनसे आग्रह किया था, "आप जो भी कार्य करें, उसे पूरी गंभीरता, लगन और ईमानदारी से करें। किसी भी काम को कभी अधूरा न छोड़ें।" (लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

AI का दौर और सोशल मीडिया की जवाबदेही

» जागरूक जनता | jagrukjanta.net

लेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को इंस्टाग्राम पर ऐसे सभिक विज्ञापन और सामग्री हटाने का निर्देश दिया है, जो बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देते हैं या उसे सुगम बनाते हैं। इससे पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से सामग्री के प्रसार के इस दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाना कितना आवश्यक है।



चिंता बढ़ाने वाली बात है कि शोषणकारी सामग्री कथित तौर पर पेड विज्ञापनों के रूप में सामने आई। चिंता केवल यूजर्स द्वारा तैयार हो रही सामग्री की ही नहीं है बल्कि स्वचालित विज्ञापन समीक्षा प्रणालियों और एआई आधारित सामग्री जांच की विश्वसनीयता की भी है, जिसे प्रकाशन से पहले कड़ी जांच से गुजरना चाहिए। मेटा ने दोहराया है कि वह ऐसे मामलों को बिल्कुल सहन नहीं करती। कंपनी ने कहा है कि वह अरबों उपयोगकर्ताओं के बीच अपमानजनक सामग्री का पता लगाने के लिए उन्नत एआई का उपयोग करती है। फिर भी यह विवाद दर्शाता है कि एआई से होने वाली जांच की भी अपनी सीमाएं हैं।

बीबीसी की एक जांच से पता चला कि मेसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिये ऐसी सामग्री बेचने के विज्ञापन

दिखाए जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम इस वर्ष ऐसी सामग्री वाले 2.74 लाख से अधिक समूहों और चैनलों को हटा चुका है मगर यह काफी लगत।

रिक्रिमंडेशन यानी सिफारिश करने वाले इंजन और विज्ञापन एल्गोरिथ्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म तक लाने और कमाई बढ़ाने के हिसाब से बनाया जाता है। मगर ये इंजन ऐसे बारीक नेटवर्कों का पता नहीं लगा पाते, जो पहचाने से बचने के लिए लगातार बदलते रहते हैं। जब विज्ञापनों के जरिये ऐसी सामग्री से कमाई की जाती है तो यह विफलता सामग्री की जांच तक नहीं रहती बल्कि प्लेटफॉर्म की वाणिज्यिक समीक्षा प्रणालियों तक चली जाती है। इससे कंपनियों के आश्वासन पर ही भरोसा करने के बजाय कंटेंट रिक्रिमंडेशन प्रणालियों और विज्ञापन मंजूरी प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच जरूरी हो जाती है।

यह चुनौती दुनिया भर में है और बढ़ती जा रही है। 2025 में अमेरिका के गैर-मालिकारी संयुक्त नैशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोर्डेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को 2.13 करोड़ साबर टिपलाइन रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं। इनमें 6.18 करोड़ चित्र, वीडियो और अन्य फाइलें बाल यौन शोषण से संबंधित थीं। लगभग 15 लाख रिपोर्ट्स जेनरेटिव एआई से जुड़ी थीं, जिससे पता लगता है कि बाल शोषण में एआई का दुरुपयोग कितना बढ़ रहा है। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूफ) ने भी 2025 में एआई से बनाए गए बाल यौन शोष संबंधी 8,029 चित्र और वीडियो की पहचान की, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत ज्यादा थे। एआई से तैयार होने वाले ऐसे वीडियो 260 गुना बढ़े हैं।

भारत के दूरसंचार नियामक को नए जनादेश की जरूरत है?

» जागरूक जनता | jagrukjanta.net

वर्ष 1997 का केंद्रीय बजट कुछ साहसिक पहलों के लिए जाना जाता है। वह बजट आने से करीब एक हफ्ते पहले तेजी से बढ़ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उसी वर्ष 20 फरवरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के नियमन का काम सरकार पर छोड़ने के बजाय स्वतंत्र निकाय को सौंपना था।



इसके पीछे की कहानी महत्वपूर्ण थी। मोबाइल टेलीफोन सेवा 1995 में शुरू हो चुकी थी और निजी कंपनियां सरकार के स्वामित्व वाली उन फोन सेवा प्रदाता कंपनियों को टक्कर देने को तैयार थीं, जिनका वर्षों से लैंडलाइन सेवा पर एकाधिकार था। योजना यह थी कि कामों को दूरसंचार विभाग और ट्राई के बीच बांट दिया जाए। दूरसंचार विभाग को नीति निर्माता और ट्राई को दूरसंचार उद्योग का प्रमुख नियामक बनाया जाना था।

किंतु लगता है कि जिस उद्देश्य से ट्राई का गठन किया गया था, वह इस सफर के दौरान पूरा नहीं हो पाया है। उद्योग जगत के पर्यवेक्षक के लिए कागज पर ट्राई नियामक संस्था होगी मगर व्यवहार में वह केवल सिफारिश करने वाली संस्था है। लाइसेंस जारी करने, संपन्नता का प्रबंधन करने और सेवा प्रदाताओं के लिए दंड तय करने का काम दूरसंचार विभाग ही करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तव में नियामक वही है। वह सेवा गुणवत्ता के मानकों के पालन समेत उपभोक्ताओं

आज नवीनतम तकनीक सभी दूरसंचार सेवाओं की रीढ़ है और डिजिटल नेटवर्क ने पारंपरिक नेटवर्कों की जगह ले ली है तब किसी भी नियामक प्रक्रिया में गति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

से जुड़े तमाम मसले देखता है और ट्राई में भर्ती के नियम भी तय करता है। आज नवीनतम तकनीक सभी दूरसंचार सेवाओं की रीढ़ है और डिजिटल नेटवर्क ने पारंपरिक नेटवर्कों की जगह ले ली है तब किसी भी नियामक प्रक्रिया में गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में कई तकनीकी मामलों में नियामक ढांचा बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए, साइबर सुरक्षा से जुड़े मसलों में गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ट्राई सहित विभिन्न संस्थाएं फैसले लेती हैं। व्हाट्सएप की नई पहल का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता अपने नाम पंजीकृत कर सकते हैं ताकि संदेश भेजते समय उनके मोबाइल नंबर गोपनीय रहें। सरकार पहले ही मेटा (व्हाट्सएप की मूल कंपनी) को यह सेवा रोकने का आदेश दे चुकी है। मामला बढ़ा तो कई मंत्रालय और नियामक हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूरसंचार क्षेत्र की बात करें तो पेचीदा डिजिटल व्यवस्था में नियमों के कार्यान्वयन में दो नियामकों के टूटने और दूरसंचार विभाग की मौजूदगी से लंबा समय लगता है और विलंब हो जाता है, जिसका असर उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ता है। ट्राई का मकसद तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा समान अवसरों के जरिये उद्योग का विकास सुनिश्चित करना था। तकनीकी प्रगति लंबे समय से मौजूद नियामकीय व्यवस्था को पछाड़ रही है और उपभोक्ता तथा उद्योग जगत खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। नियामक और सरकार के बीच

घूमते रहने वाले निर्णयों के कारण होने वाले नियामकीय विलंब को प्रक्रिया सुगम बनाकर टाला जा सकता है। स्पैम कॉल और अवांछित संचार को रोकना ऐसा ही उदाहरण है, जहां नियामकीय व्यवस्था कई तरह से बदली है किंतु उपभोक्ताओं को अब भी राहत नहीं मिली है और उद्योग यही सोच रहा है कि आगे क्या होगा।

वर्ष 1997 में ट्राई के गठन का एक प्रमुख कारण यह आशंका थी कि यदि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड में स्वामित्व रखने वाली सरकार निजी कंपनियों के लिए खोले गए क्षेत्र का विनियमन जारी रखती है तो हितों का टकराव हो सकता है। आज सरकारी स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल के अलावा वोडाफोन आइडिया में भी सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि सरकार वोडाफोन आइडिया में प्रवर्तक नहीं है मगर हितों के टकराव की आशंका बनी हुई है क्योंकि सरकार ही लाइसेंस देने वाली संस्था है। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियामकों को देखें तो ट्राई के अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता बेहतर ढंग से समझी जा सकती है। द फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ऑफ अमेरिका (1934 में स्थापित), द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफकॉम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम (2003 में स्थापित), ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशंस एंड मीडिया अथॉरिटी (2005 में स्थापित) ही लाइसेंस देने से लेकर स्पेक्ट्रम संभालने तक हर चीज के लिए व्यापक विनियामक और शक्ति केंद्र हैं।

देश का दूरसंचार क्षेत्र 1997 से अब तक काफी बदल चुका है। फरवरी 1997 में जब ट्राई की स्थापना हुई थी तब भारत में कुल 148.8 लाख टेलीफोन ग्राहक थे, जिनमें केवल 3.4 लाख ग्राहक सेल्युलर मोबाइल सेवाओं का उपयोग करते थे। प्रति 100 व्यक्तियों पर केवल 1.5 का दूरसंचार घनत्व था।

ओपिनियन

अलनीनो अटैक: कमजोर मानसून से डगमगाएगी अर्थव्यवस्था

» जागरूक जनता | jagrukjanta.net

जलवायु परिवर्तन और प्रशांत महासागर में तेजी से फैल रहे 'अलनीनो' देश-दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अलनीनो के असर के चलते इस बार जून का महीना पिछले सी वर्षों में तीसरा सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया है। देश के अंदरूनी हिस्सों में मानसूनी हवाओं की रफ्तार काफी धीमी रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा और मध्य भारत सहित कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो



सकती है। अगर ये उम्मीद भी अधूरी रही तो आम आदमी की थाली पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में इस साल जून माह में अलनीनो के प्रभाव के कारण मानसून की बारिश में सामान्य से 42 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और वैश्विक मौसम विज्ञानियों के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से सक्रिय हो रहा यह अलनीनो साल के अंत तक सुपर

अलनीनो का रूप ले सकता है। आगामी महीनों में कमजोर मानसून और भीषण गर्मी का संकट गहराने की भी आशंका है। ऐसा हुआ तो इस अलनीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस सीजन (जून से सितंबर) में दीर्घावधि औसत की केवल 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान भी जताया है। मानसून की इस सुस्ती के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय मौसमी बदलाव जिम्मेदार हैं। देशभर के कई हिस्सों में मानसून के समय पर न पहुंचने के पीछे मौसम विज्ञानियों ने कई कारण गिनाए हैं। पहला कारण है कि मानसून को आगे धकेलने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्र की जरूरत होती है। इस बार ऐसा कोई प्रभावी सिस्टम नहीं बना, जिससे मानसूनी हवाओं की गति थम गई। दूसरा कारण है कि जून महीने की शुरुआत में उत्तर-पश्चिम भारत में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे। इन हवाओं ने मानसूनी दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के साथ खींचतान पैदा की, जिससे मानसून का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ। तीसरा कारण है कि राजस्थान में बारिश लाने में अरब सागर से आने वाली नमी से भरी हवाओं की बड़ी भूमिका होती है। इस बार शुरुआती चरण में ये पश्चिमी हवाएं कमजोर रहीं, जिससे हवा में पर्याप्त नमी का स्तर नहीं बन पाया। चौथा कारण है कि मानसून की उत्तरी

प्रशांत महासागर में तेजी से सक्रिय हो रहा यह अलनीनो साल के अंत तक सुपर अलनीनो का रूप ले सकता है। आगामी महीनों में कमजोर मानसून और भीषण गर्मी का संकट गहराने की भी आशंका है। ऐसा हुआ तो इस अलनीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

सीमा देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में करीब एक सप्ताह से अधिक समय तक एक ही जगह पर स्थिर रही, जिससे इसका उत्तर-पश्चिम की तरफ मूवमेंट रुक गया। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि इस बार मानसून की धीमी चाल के पीछे अलनीनो का सीधा हाथ है। अलनीनो एक ऐसी वैश्विक मौसमी परिघटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। जब प्रशांत महासागर में यह गर्मी बढ़ती है, तो यह वैश्विक वायुमंडल के चक्र को बदल देती है। इसके प्रभाव से भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बादलों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारतीय मौसम

विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत पर अलनीनो का साया साफ देखा जा रहा है, जिसने मानसून के आगमन को आगे बढ़ा दिया है। मानसून के देरी से आने का जनजीवन पर गहरा असर पड़ेगा।

भारत की लगभग आधी कृषि भूमि सिंचाई के लिए सिंधे तौर पर मानसूनी बारिश पर निर्भर है। ऐसे में अल-नीनो के कारण इस बार कृषि क्षेत्र को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में देरी के कारण खरीफ फसलों पर संकट है। धान, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी मुख्य खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। करीब 12 से अधिक राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में खेती पर इसका सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है। पानी की कमी से न सिर्फ फसलें, बल्कि पशुओं के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो सकता है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जुलाई के पहले सप्ताह में भी अच्छी बारिश नहीं होती है, तो दालों और तिलहन के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

असल में अलनीनो एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इस अत्यधिक

गर्मी के कारण वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित होता है, जिससे भारत की तरफ आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि अलनीनो वाले वर्षों में भारत में मानसूनी बारिश में भारी कमी आती है और सूखे की स्थिति पैदा होती है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस अलनीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस अलनीनो चक्र के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2032 तक 94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संघी आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं खाद्य उत्पादन घटने से बाजारों में अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ और अधिक बढ़ेगा। साथ ही बिजली संकट की आशंका जताई गई है। माना जा रहा है कम बारिश के कारण देश के जलाशयों का स्तर घटेगा, जिससे हाइड्रो पावर (जलविद्युत) उत्पादन प्रभावित होगा और गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। फिलहाल संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले ही कमर कस ली है और इतरजैसी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार ने देश के 150 से 200 से अधिक संवेदनशील जिलों की पहचान की है, जहां अलनीनो का असर सबसे खतरनाक हो सकता है।

ज्योतिर्विद्व अक्षय शास्त्री साकेत पंचांग, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

जागरूक जनता पंचांग, नक्षत्र, तिथि, चौघडिया

सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथि बुधवार, 8/7/2026

सूर्योदय : 05:43 सूर्यास्त : 19:20 चन्द्रोदय : 24:30 चन्द्रास्त : 13:04 शक संवत् : 1948 पराभव विक्रम संवत् : 2083 सिद्धार्थी अमान्ता महीना : ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि : आषाढा सूर्य राशि : मिथुन चन्द्र राशि : मीन पक्ष : कृष्ण तिथि : अष्टमी, 12:17 तक वार : बुधवार द्विक ऋतु : वर्षा द्विक अयन : दक्षिणायन कलियुग : 5127 वर्ष

नक्षत्र, योग, करण नक्षत्र : रेवती, 05:19 तक प्रथम करण : कौवाला, 12:17 तक योग : अतिगदा, 12:31 तक द्वितीय करण : तैत्तिल, 23:30 तक

शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त : 04:09 एम से प्रातः सन्ध्या : 04:29 एम से अभिजित मुहूर्त : कोई नहीं विजय मुहूर्त : 02:45 पी एम से गोधूलि मुहूर्त : 07:21 पी एम से सायाह सन्ध्या : 07:23 पी एम से अमृत काल : 01:38 पी एम से निशिता मुहूर्त : 12:06 एम, जुलाई 09 से

निवास और शूल दिशा शूल : उत्तर में राहु काल वाल दक्षिण-पश्चिम में होमाहुति : गुरु - चहु कुंभ वक्र: तल

चौघडिया दिन का चौघडिया रात का चौघडिया

आज अष्टमी आज ठौन सा कार्य करें अष्टमी : संक्राम, वास्तु, शिल्प, लेखन, खी, रत्न धारण, आभूषण खरीदना व सब अष्टमी को शुभ हैं।

बुधवार को क्या करें बुधवार की प्रकृति चर और सौर्य मानी गई है। यह भगवान गणेश और दुर्गा का दिन है। कर्मजोर् मालिक वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए।

राशिफल ज्येष्ठ, कृष्ण, अष्टमी, 2083 बुधवार, 8 जुलाई - 14 जुलाई, 2026

मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, लो वाणी पर नियंत्रण रखें। क्लेश से बचें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवेक से कार्य करें। शेरप मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं।

रिफाइन्री सहित 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

डबल इंजन सरकारें शिलान्यास ही नहीं, परियोजनाओं को धरातल पर करती हैं पूरा- प्रधानमंत्री मोदी

जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

जयपुर/पचपदरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों ना हो, नया भारत अपने संकल्पों से ना पीछे हटता है ना ही अपनी रफ्तार कम करता है। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर नए भारत की इच्छा-शक्ति और प्रयास भारी पड़े। प्रधानमंत्री पचपदरा में आयोजित एक भव्य समारोह में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइन्री सहित 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।

- कार्यक्रम की विशेष झलकियां
समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजकीय सेवा में नवनियुक्त युवाओं को अभिभूतन पत्र सौंपे।
रिफाइन्री, जयपुर मेट्रो सहित राजस्थान की विकास गाथा पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री ने एलपीजी टैंकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने रिफाइन्री की मेन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली और युवा कार्मिकों एवं प्रबंधन से संवाद किया।
उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई।
प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रिफाइन्री परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

डिलीमेंटिक पावर का क्या सरकारात्मक इस्तेमाल

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने दूरदर्शी नीति, प्रभावी रणनीति और मजबूत कूटनीति के बल पर देश को ऊर्जा संकट से सुरक्षित रखा। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लेते हुए संकट का समय रहते सटीक आंकलन किया और प्रभावी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों के संतुलित प्रयोग, डिलीमेंटिक पावर के सरकारात्मक इस्तेमाल और एक दायर से चल रही दूरदर्शी नीतियों के कारण देश इस अप्रत्याशित चुनौती से उबर पाया।

जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे थे, आज वे निराश

उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं, तब दिन-रात मेहनत करते हुए स्थिति को संभालने के लिए नीतिगत और कूटनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को देश की क्षमताओं और सुझबुझ पर भरोसा था। वे इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने अफवाह, झूठ और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया और देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया। देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे थे, इसके लिए भविष्यवाणी करने लग गए थे, वो आज निराश हैं।

वैश्विक संकट के समय दिखा भारत की डिलीमेंटिक पावर का जलवा

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 'नागरिक देवो भवः' की भावना से काम करती है। हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। युद्ध से पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिलीमेंटिक पावर दिखाने और युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरतों की करीब 60 प्रतिशत एलपीजी अल्प देशों से आयात की जाती थी। इसमें से भी 90 प्रतिशत एलपीजी खाड़ी देशों से आ रही थी और युद्ध के हालात ने इसे लगभग बंद कर दिया, लेकिन हमने संकट शुरू होते ही रिफाइन्रीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइन्रीज को रसोई गैस-एलपीजी बनाने के लिए कहा गया। जिससे वसाह भर में एलपीजी उत्पादन 35 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन हो गया। साथ ही बहुत कम समय में करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ा गया। इन प्रयासों ने घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ने दिया। अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपए और उच्चला सिलेंडर 650 रुपए से भी कम में दिया जा रहा है। वहीं, कॉमर्सियल गैस की कीमतों में बड़ी कटौती भी की गई है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से रुढ़ आर्थिक की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से 120 डॉलर तक पहुंच गई थी। दुनिया के कई देशों में डीजल-पेट्रोल की कीमतें 50 प्रतिशत तक बढ़ गईं, तो कई देशों में डीजल-पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन के लिए भी ऐसे हालात नहीं आए। दूर-दराज इलाकों में भी सप्लाय को कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच डीजल-पेट्रोल में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई। वहीं, एक्सहाइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी लाकर हमने जनता पर बड़ा बोझ नहीं पड़ने दिया।

सुरक्षित महसूस कर रहे छोटे-बड़े उद्योग और किसान

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। यूरे'न युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया बोरी की कीमत 3 हजार रुपए से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हमने आपूर्ति मार्ग प्रभावित होने पर वैकल्पिक रास्ते तलाशे और दूसरे देशों से उर्वक खरीदने की पहल की। साथ ही घरेलू उत्पादन पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी देते हुए किसानों को केवल 300 रुपये में यूरिया उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया गया, जिसके

रिफाइन्री राजस्थान की भाग्यरेखा, देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का नया आधार- मुख्यमंत्री भजनलाल



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

तहत 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण दिया गया और इस पर शत-प्रतिशत सरकारी गारंटी प्रदान की गई। ऐसे ही अनेक फैसलों के कारण आज हमारे छोटे-बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती सरकार में ठप रहा काम, डबल इंजन सरकार में तेजी से पूरी हुई रिफाइन्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामिमान तभी ऊंचा रह सकता है जब हम आत्मनिर्भर हों। इस दृष्टि से यह रिफाइन्री आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह रिफाइन्री हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी तथा राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारें केवल शिलान्यास नहीं करती, बल्कि परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर जनता को समर्पित भी करती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राजस्थान रिफाइन्री के लिए एमओयू हुआ था, लेकिन वर्ष 2018 से 2023 तक राजस्थान को पूर्ववर्ती सरकार के असहयोग के कारण काम लगभग ठप रहा। डबल इंजन सरकार आते ही इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज इसका लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई

इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण-शिलान्यास

- एचपीसीएल राजस्थान रिफाइन्री
जयपुर मेट्रो फेज-2
पावरग्रिड बाइमेर-प्रथम ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावरग्रिड ब्यावर-दोसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
1000 मेगावाट वीकानेर सोर विद्युत परियोजना
300 मेगावाट करणीसर सोलर पावर प्लांट वीकानेर
4-लेन जोधपुर रिंग रोड स्टेसन-11
चूरू-सादुलपुर रेल मार्ग
चूरू-रतनगढ़ रेल मार्ग।

अंतर्गत हियनिकूड बैराज से पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से सोकर, झुंझुन, चूरू तथा आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेगुला, लखवार और किशाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को और लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए संचालित अभियानों से प्रदेश में भूजल स्तर सुधारने में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर काम करते हुए राजस्थान में विध्वस्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यप्र मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में डेढ़ लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान में किसानों को 65 हजार से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। वहीं, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए 'जल संचय, जन भागीदारी' बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब 25 लाख और राजस्थान में सवा लाख से ज्यादा सोलर पंप बनाए गए हैं। उन्होंने सरकारी नियुक्ति प्राप्त करने वाले प्रदेश के 54 हजार युवाओं को उच्चल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

हर व्यक्ति तक जनहितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही डबल इंजन सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता का विश्वास प्राप्त कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया इतिहास रचने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 12 वर्षों से विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक तक जनहितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्प एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रिफाइन्री राजस्थान की भाग्यरेखा के साथ-साथ पूरे देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का नया आधार बनेगी। यह परियोजना प्रदेश के समग्र विकास को हथकौड़ी बन सिद्ध होगी और पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योगों का प्रमुख हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से नए उद्योगों के निवेश को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी तथा लाखों युवाओं के लिए पर्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

जयपुर मेट्रो फेज-2 से राजस्थान के विकास को मिलेगी और गति - प्रधानमंत्री मोदी



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। आज इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कर्मियों से हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्माण के उपरांत इसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के अन्तर्गत प्रहलादपुरा से टोंडी मोड तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर सीतापुरा से लेकर वीकेआईए तक के औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए जयपुर की जीवनरेखा के रूप में कार्य करेगा। इस कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन होंगे और परियोजना की कुल लागत 13 हजार 37 करोड़ रुपये से अधिक है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50:50 साझेदारी वाली संयुक्त कंपनी है। यह फेज-2 कॉरिडोर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, टॉक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना में एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन भी शामिल होगा, जिससे शहर में एकोकृत और निरंतर मेट्रो नेटवर्क सुनिश्चित होगा।

12 किमी. के पहले पैकेज का एलओए जारी

उल्लेखनीय है कि जयपुर में फेज-1 के तहत उत्तर-पश्चिम कॉरिडोर पर मानसरोवर से बड़ी चौड़ाई तक 11.64 किलोमीटर लंबी मोटो सेवा संचालित है, जिसमें 11 स्टेशन हैं। प्रस्तावित फेज-2 उत्तर-दक्षिण दिशा में इस नेटवर्क को और विस्तार देगा। केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के फेज-2 के पहले पैकेज में 918.04 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों के लिए एलओए (स्वीकृत पत्र) जारी कर दिया है। इसमें प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन (प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कलां, बीलवा, गोनरे मोड, सीतापुरा, जईसीसी, कुंआ मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला) का डिजाइन एवं निर्माण पूर्ण किया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 के डिगो की ओर जाने वाली स्पर लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के साकार होने से जयपुर शहर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। जिससे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण सुनिश्चित होगा। साथ ही, जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत चाकस एवं चौमू सहित आस-पास के कर्मों को निकटतम प्रहलादपुरा और टोंडी स्टेशनों से जोड़ने के लिए बसें चलाने की योजना भी बनाई जाएगी।



मुख्यमंत्री भजनलाल की केंद्रीय मंत्री जोशी से शिष्टाचार मुलाकात
जयपुर @ जागरूक जनता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से शिष्टाचार मुलाकात की। इसके पश्चात उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस दौरान राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं, आगामी विकास परियोजनाओं और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रदेशभर में एक माह तक चलेगा विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान

जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
जयपुर। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान में एक माह का विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की प्रेरणा तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरीओम अत्री की



जयपुर @ जागरूक जनता। हवामहल विधायक, हाथोज धाम महाराज श्री बालमुकुन्द आचार्य जी अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करते हुए।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इंटरडिसिप्लिनरी M.Sc. प्रोग्राम्स के करिकुलम रिफॉर्म पर दो दिवसीय वर्कशॉप आयोजित

जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
जयपुर। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा "करिकुलम रिफॉर्म फॉर इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स" विषय पर दो दिवसीय वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य संस्थान में संचालित छह नए इंटरडिसिप्लिनरी M.Sc. प्रोग्राम्स के करिकुलम को कॉम्प्लेक्सि-बेस्ड एवं आउटकम-ओरिएंटेड एजुकेशन के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना था। कार्यक्रम में प्रो. पी. हेमंता कुमार ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इन्वैशन तथा रिसर्च-ओरिएंटेड पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप करिकुलम विकसित कर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना संस्थान की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में कुलसचिव प्रो. अनीता शर्मा, प्रो. मीता कोटेचा, प्रो. सर्वेश कुमार अग्रवाल, प्रो. कमलेश शर्मा, प्रो. कनिंका वर्मा, प्रो. श्रीनाथ वैद्य, डॉ. विनोद कुमार एम.बी., डॉ. गौरव फुल, प्रो. अचिंत गुप्तानी, डॉ. परमवीर शेखावत, प्रो. जेराल्डिन जैन तथा डॉ. बिष्णु चौधरी सहित अन्य विशेषज्ञों ने सक्रिय रूप से अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए। दो दिवसीय वर्कशॉप के दौरान छह इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स-आयुर्वेद डाइट एंड न्यूट्रिशन, आयुर्वेद मैनुस्क्रिप्टोलॉजी, आयुर्वेद प्रिंटेड काउंट्रीलॉजी, मर्मांशुली एंड स्पेसिअल मेडिसिन, सौंदर्य आयुर्वेद तथा वृक्षायुर्वेद के लिए समानांतर टैक्निकल सेरॉस आयोजित किए गए। इन सेरॉस में सभी विभागाध्यक्षों, फैकल्टी

कुंडली विश्लेषण में सटीक फलादेश से छाप अक्षय शास्त्री, मिला "सेंटर ऑफ एक्सिलेंस"

जागरूक जनता
 jagrukjanta.net
डीडवाना-कुचामन। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जसवंतगढ़ (डीडवाना-कुचामन) द्वारा आयोजित द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठि में "वर्तमान परिदृश्य में तंत्र-मंत्र-यंत्र की प्रासंगिकता" विषय पर देशभर से आए विद्वानों, आचार्यों, शोधार्थियों एवं ज्योतिष विशेषज्ञों ने सहभागिता की। इस प्रतिष्ठित आयोजन में श्री साकेत पंचांग, बूढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए अक्षय शास्त्री ने अपनी विद्वता का उत्कृष्ट परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान कुंडली विश्लेषण एवं फलादेश का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को विभिन्न जन्म-कुंडलियों का विश्लेषण कर सटीक निर्णय प्रस्तुत करना था। इस चुनौतीपूर्ण सत्र में अक्षय शास्त्री ने अपने गहन शास्त्रीय अध्ययन, सूक्ष्म विश्लेषण तथा सटीक फलादेश से उत्पन्न विद्वानों को प्रभावित कर दिया। उनके उत्तरों की शुद्धता एवं तार्किकता की सभी विशेषज्ञों ने सराहना की। अक्षय शास्त्री के उत्कृष्ट प्रदर्शन, कुंडली विश्लेषण की अद्भुत सटीकता एवं शास्त्रीय दक्षता को देखते हुए आयोजकों द्वारा उन्हें "सेंटर ऑफ एक्सिलेंस" से सम्मानित किया गया।

मृग की उन्नत किस्म MH-1142 का अग्रिम पक्ति प्रदर्शन आयोजित
कल्याणपुर (बालोतरा) @ जागरूक जनता। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), गुडामालानी द्वारा दलहन आत्मनिर्भर मिशन के अंतर्गत देश में दलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों को मृग की नवीन एवं उन्नत उत्पादन तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से कल्याणपुर में मृग की उन्नत किस्म MH-1142 का समूह अग्रिम पक्ति प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. प्रदीप पगारिया ने किसानों को बताया कि उन्नत किस्म MH-1142 अधिक उत्पादन क्षमता, बेहतर दाना गुणवत्ता तथा स्थानीय जलवायु के अनुरूप अच्छी अनुकूलता रखने वाली किस्म है। किसानों को बीज उपचार, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर बुवाई, खरपतवार नियंत्रण की वैज्ञानिक जानकारी दी। केंद्र के प्रसार वैज्ञानिक डॉ. विकास कुमार ने बताया कि समूह अग्रिम पक्ति प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेत पर नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन कर उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है। कीट वैज्ञानिक डॉ. बाबूलाल जाट ने एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन पर जानकारी दी।

@ दीया दुलार



जयपुर @ जागरूक जनता। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर स्थित बालिका एवं शिशु गृह में बालिकाओं और नन्हें-मुन्ने बच्चों के साथ बितायें आत्मीय पल।

मुख्य सचिव ने राजस्थान में संचालित विकास योजनाओं के सम्बंध में केन्द्रीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर प्रगति से अवगत करवाया

जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नई दिल्ली में केन्द्र सरकार के कई आला अधिकारियों से भेंट कर राज्य के विकास से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की और अद्यतन प्रगति से अवगत करवाया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर के साथ भेंट कर राजस्थान में औद्योगिक निवेश, रोजगार संवर्धन, विकास, विभिन्न केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं, नवाचारों की सफलता की चर्चा की। मुख्य सचिव ने बताया कि गत 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान यात्रा में किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास विकसित राजस्थान@2047

आमेर में पर्यटन सीजन की तैयारियों की समीक्षा

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध व्यवस्थाओं के निर्देश



जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पर्यटन, पुरातत्व, जयपुर नगर निगम, यातायात पुलिस, पर्यटन पुलिस तथा एडीएमए (ADMA) के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में सुगम यातायात प्रबंधन और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान आमेर क्षेत्र में ट्रेफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के निर्बाध आवागमन, आवश्यक नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें, ताकि आमेर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को सुगम, सुस्थित और व्यवस्थित पर्यटन सुविधाएं मिल सकें।

और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों को पूरा करने में बहुल महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मुख्य सचिव ने केन्द्रीय केबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) डॉ. मनोज गोविल के साथ बैठक कर राजस्थान में डीरेग्यूलेशन और कम्प्लायंस रिडक्शन फेज-2 की प्रगति की जानकारी दी। सेवा तीर्थ में हुई इस बैठक में डॉ. मनोज गोविल ने राजस्थान की प्रशांसा करते हुए उम्मीद जताई कि फेज-1 की तरह फेज-2 में भी राजस्थान टॉप राज्यों में शामिल रहेगा। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राईजिंग इंडिया के अंतर्गत राजस्थान में डीरेग्यूलेशन और कम्प्लायंस रिडक्शन को सफलता से ईज ऑफ

कपासन में 18 अक्टूबर को होगा उदयपुर संभाग का दूसरा मंसूरी इज्जतमाई शादी सम्मेलन

13 सितम्बर तक होंगे पंजीयन
जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
कपासन। दरगाह हजरत दीवाना शाह सा. र.अ. परिसर में आगामी 18 अक्टूबर (रविवार) को आयोजित होने वाले उदयपुर संभाग के दूसरे मंसूरी इज्जतमाई शादी सम्मेलन की तैयारियों एवं रूपरेखा को लेकर मंसूरी एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी उदयपुर की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सोसायटी के सदर अब्दुल लतीफ मंसूरी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावत-ए-कुलाय-ए-पाक से हुआ। सोसायटी के सचिव जाह्द मोहम्मद मंसूरी ने बताया कि सम्मेलन पीर तरीकत हजरत डॉ. सय्यद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी उर्फ कादरी मियां (सब्रबाहे आला, मखदूम अशरफ मिशन, पख्खा शरीफ, बंगाल) की कयादत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रत्येक जोड़े के लिए लड़का एवं लड़की पक्ष से अलग-अलग 21-21 हजार रुपये पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है। नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग के आवश्यक उपहार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 13 सितम्बर तक की गई है। बैठक में सोसायटी के खजांची मोहम्मद युसुफ मंसूरी (इंजीनियर), पूर्व उपसरपंच आजाद हुसैन सावरिया, मोहम्मद युसुफ, फ़िरोज मोहम्मद (नाथद्वारा), आलानदी मंसूरी (कुवारिया), निसार मोहम्मद अगवान (भिंडर), एडवोकेट शाहहसन मंसूरी (मांगरोल, निम्बाहेड़ा), एडवोकेट शरीफ मोहम्मद मंसूरी (भीमगढ़), मोहम्मद अब्बास अशरफी, मोहम्मद इस्माईल गौरी सहित अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 20 तक कर सकेंगे आवेदन एवं पंजीयन

जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने तथा विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर राजकीय (नवीन) एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने तथा इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए पूर्व में 30 जून 2026 की तिथि निर्धारित थी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों एवं संस्थाओं की सुविधा को देखते हुए अब यह तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 कर दी गई है।

माधव तित्त के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक आयोजित



आबूरोड @ जागरूक जनता। माधव विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में बोर्ड ऑफ स्टडीज 2026-27 के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित शिक्षा तथा नए कृषि कार्यरत मां को शामिल करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अध्यक्षता प्रो. (डॉ.) गोतम सिंह ने की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीआर) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. आर.बी. शर्मा तथा आरबीएस कॉलेज, बिचपुरी (आगरा) के कृषि प्रसार विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) विजय कुमार शर्मा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक प्रो. (डॉ.) देवेन्द्र मुजाल, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट संकाय के अध्यक्षता प्रो. (डॉ.) गंगा सिंह चौहान, प्रो. (डॉ.) जिनार सोनी, योग विभागाध्यक्ष अभिजित सिंह चौहान, एनसीसी समन्वयक डॉ. उर्वशी पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमित सिंह, सहायक प्राध्यापक डॉ. पार्वती कुमावत एवं डॉ. आलोक कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद, जैसलमेर (राज.) 345001

क्रमांक: भूमि/2026-27/1347 दिनांक 06/07/2026
प्रसारित नोटिस उजरदारी :-
 श्रीमती शांता चाण्डक पत्नी श्री लुणकरण चाण्डक जाति माधेश्वरी निवासी महाजनों का बास, ग्राम लाठी जिला जैसलमेर द्वारा एक आवेदन-पत्र, विक्रय पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवासीय भूखण्ड संख्या डी-231 से लगनी अधिक भूमि माप 18 गुण 50 कुल 900 वर्गफीट वाके जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना जैसलमेर जो की श्री हिमांशु पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपुरहित निवासी उचला वास, थोब जिला जोधपुर से जरीये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से क्रय किया गया है। उक्त भूखण्ड का नामान्तरण श्रीमती शांता चाण्डक पत्नी श्री लुणकरण चाण्डक जाति माधेश्वरी निवासी महाजनों का बास, ग्राम लाठी जिला जैसलमेर द्वारा अपने नाम से दर्ज करवाना करवाना चाहती है। अतः इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / पार्टी को कोई उजर ऐतराज तो वह इस कार्यालय में 7 दिवस के भीतर पेश करे अन्यथा बाद न्याय कोर्ट उजर ऐतराज मान्य नहीं होगा तथा नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी सूचित रहे।
आयुक्त
नगर परिषद जैसलमेर

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट का फैसला

38 दोषियों की फांसी और 11 को उम्रकैद, पीड़ितों को मिलेगा 10-10 लाख मुआवजा

जागरूक जनता नेटवर्क
 jagrukjanta.net
अहमदाबाद। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें 38 आतंकीयों को फांसी की सजा और 11 अन्य को उम्रकैद दी गई थी। अदालत ने दोषियों की तरफ से दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जस्टिस एवार्ड कोगजे और समीर दवे की पीठ ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोषसिद्ध और सजा दोनों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सदस्यों को इस हमले का दोषी ठहराया था। **56 लोगों की हुई थी मौत**
अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को महज 70 मिनट के भीतर 21 अलग-अलग जगहों पर एक के बाद एक बम धमाके हुए। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। हमलावरों ने धमाकों में घायल लोगों का इलाज कर रहे अस्पतालों को भी निशाना बनाया था, जिससे हमले की भयावहता और बढ़ गई थी। इन धमाकों की इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने इस मामले में रेपेरेट ऑफ रेपेय श्रेणी का मानते हुए 38

SIT ने सुलझाया केस
बता दें कि धमाकों के बाद गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने SIT बनाई। पुलिस ने 19 दिनों में कई राज्यों से आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए गिरफ्तारियां कीं। बता दें कि आतंकीयों ने अहमदाबाद के अलावा सुरत में भी बम लगाए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फट नहीं पाए। **कोर्ट में पेश किए गए थे 6 हजार पन्नों का दस्तावेज**
कोर्ट में इस बम धमाके की जांच में करीब 6 हजार पन्नों का दस्तावेज पेश किए गए थे। वहीं 1100 से ज्यादा गवाहों का बयान भी कोर्ट में दर्ज हुए थे। सुनवाई के दौरान 7 जज भी बतल गए थे।



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

विकास के पथ पर गतिमान राजस्थान

माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

के कर कमलों द्वारा

1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास/ उद्घाटन/ लोकार्पण

राजस्थान रिफाइनरी

- राजस्थान रिफाइनरी का राष्ट्र को समर्पण
- 79 हजार करोड़ से अधिक की लागत से तैयार ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी
- देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर
- रिफाइनरी की क्षमता 9 एमएमटीपीए एवं 29 प्रसंस्करण इकाइयाँ
- 35 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार एवं एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार

यमुना जल परियोजना

- यमुना जल MoA आभार
- 34,102 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना
- राजस्थान को यमुना जल मिलाने की 30 वर्षों की मांग पूरी
- शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं अन्य क्षेत्रों को मिलेगा भरपूर पानी
- 75 लाख आबादी को लाभ

जयपुर मेट्रो फेज-2

- 13 हजार करोड़ की लागत के जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास
- 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर
- प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन
- जयपुर के सीतापुरा से लेकर वीकेआईए तक यातायात सुगम
- शहरी विकास और समय की बचत

नियुक्ति पत्र वितरण

- 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण
- सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्तियाँ
- 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियाँ
- 1 लाख 45 हजार भर्तियाँ प्रक्रियाधीन
- 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियों का वार्षिक कलैण्डर जारी

ऊर्जा, सड़क, नागरिक उड्डयन एवं रेलवे की विकास परियोजनाएं

8 कार्य | 13 हजार 923 करोड़ रुपए

शनिवार, 4 जुलाई, 2026 | प्रातः 9:30 बजे | पचपदरा, ज़िला बालोतरा, राजस्थान



गरिमाययी उपस्थिति

श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे

राज्यपाल, राजस्थान

श्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्रीमती दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री, राजस्थान

डॉ. प्रेम चंद बैरवा

उप मुख्यमंत्री, राजस्थान



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नई दिल्ली दौरा

6 केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर ऊर्जा, मेट्रो, जल परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि से जुड़े मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार देर रात और मंगलवार को प्रदेश के हितों की पैरवी और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी समन्वय के लिए 6 केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, शहरी विकास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की प्रगति को लेकर केन्द्रीय मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को व्यवस्थित रूप से धरातल पर लागू किया गया है। पहले ही दिन से यहां सभी मजदूरों को कार्य उपलब्ध करने के साथ ही हर गांव का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही ग्राम विकास चौपालों की भी

सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गांवों में जाकर स्वयं लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली, राज्य में अन्न भंडारण क्षमता के विस्तार एवं आधुनिक वेयरहाउस विकसित करने पर चर्चा की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के क्षेत्र में राजस्थान को उल्लेखनीय प्रगति को लेकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की यह उपलब्धि केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। बैटक के दौरान स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति प्रदान करने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं को लेकर सकारात्मक संवाद किया। केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामला मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ ही केन्द्र और राज्य समन्वय को लेकर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि सोमवार देर रात मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राजस्थान में चल रही विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की प्रगति को लेकर विचार-विमर्श किया था।

भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री गौतम का किया स्वागत



माउंट आबू @ जागरूक जनता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम एव राजस्थान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारिंह सिंह जोधा का मंगलवार को पहली बार आबूराज आगमन हुआ। संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि हमें बूध को सबसे मजबूत इकाई बनाना है। केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और पार्टी के विचारों को घर-घर तक ले जाना ही हमारा संकल्प है। संगठन महामंत्री ने माउंट आबू के कार्यकर्ताओं से संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अनुशासन, समन्वय और सक्रियता के साथ काम करने पर विशेष बल दिया। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। संगठन की मजबूती से ही हम जनता का विश्वास जीत सकते हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने सिरौही जिले की समस्त संगठनात्मक कार्य की जानकारी महामंत्री के सामने साझा करते हुए कहा कि जिला सिरौही एवं माउंट आबू मंडल संगठन द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों एवं अभियान में अग्रिम भूमिका में कार्य कर रहा है। बैठक में सांसद लुब्धामरा चौधरी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, जिला महामंत्री नरपत सिंह राणावत, जयपुर सिंह, जिला मंत्री गीता अग्रवाल, समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे।

बिरला शिक्षा केंद्र में छात्रों को दिए आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा के टीप्स



जागरूक जनता नेटवर्क jagrukjanta.net

चित्तौड़गढ़। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "महिला सुरक्षा संकल्प अभियान" के तहत बिरला शिक्षा केंद्र में छात्रों के लिए जागरूकता एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण तथा कानून और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के प्रभुलाल एवं विजयता ने छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की सदस्य प्रियंका एवं दुर्गा ने छात्रों को आत्मरक्षा के व्यावहारिक गुर सिखाते हुए संकट की स्थिति में घबराने के बजाय आत्मविश्वास और सूझबूझ से कार्य करने की सीख दी। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों ने पुरे उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया। विद्यालय की प्राचार्या रेखा यादव ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने वर्तमान समय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी विशेष प्रकाश डाला।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की निगरानी से जुड़ी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के नियम सख्त

बिल्डर को आशियाने की हर ईंट का देना होगा हिसाब

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की निगरानी से जुड़ी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब बिल्डरों को निर्माण कार्य की प्रगति ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति, खरीदारों और बुकिंगकर्ताओं से मिली राशि, फंड का स्रोत, रेरा रिटेंशन बैंक खाते में जमा, निकासी व बैंक खाते का पूरा हिसाब निर्धारित फॉर्म में देना होगा। इसके अलावा परियोजना में सड़क, पार्क, क्लब हाउस, सीवरेज, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के विकास की

पैसे का ब्योरा भी जरूरी

बिल्डरों को यह भी बताना है कि प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा कहां से आया है। प्रोजेक्ट शुरू करते समय अनुमानित फंड के स्रोत और हर तिमाही यह जानकारी देनी होगी कि वास्तव में पैसा किन-किन स्रोतों से जुटाया गया। जानकारी को पोर्टल पर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

मूलधन और ब्याज को लेकर नियम स्पष्ट

रेरा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना की विकास लागत (डवलपमेंट कॉस्ट) में केवल बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी या अन्य संस्थाओं से लिए गए लोन पर देय ब्याज ही शामिल माना जाएगा। लोन का मूलधन (प्रिंसिपल) लौटाने की राशि को विकास लागत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह निर्माण पर किया गया खर्च नहीं है।

अपने व्यापार को दें नई पहचान और बढ़ाएं अपनी बिक्री

आज ही बुक करें अपना विज्ञापन

जो दिखेगा वही बिकेगा

सकारात्मक हिट्टी अखबार

जागरूक जनता

राजस्थान | उत्तर प्रदेश | मध्य प्रदेश | दिल्ली | हरियाणा

राजस्थान के साथ-साथ 4 राज्यों में प्रसारित होगा विज्ञापन

कलासीफाइड विज्ञापन

शादी-विवाह

आम सूचना

शुभकामना एवं बधाई संदेश

खोया-पाया

संस्थान एवं स्कूल / कॉलेज विज्ञापन

नाम परिवर्तन

संपत्ति एवं अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन

हमारे यहाँ उपलब्ध विज्ञापन श्रेणियाँ

98293 29070

jagrukjantanews@gmail.com

99280 22718

www.jagrukjanta.net

आज ही अपना विज्ञापन बुक करें

“जागरूक जनता” आपके व्यापार की तरक्की का विश्वसनीय साथी

द्वैतर एवं गैर-परिवहन दोपहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत

आरसी नवीनीकरण में अतिरिक्त शुल्क में विशेष छूट

व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नए दिशा-निर्देश भी लागू



जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों, वाहन स्वामियों एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान ने एक ओर कृषि ट्रैक्टर एवं गैर-परिवहन श्रेणी के दोपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) के नवीनीकरण में देरी पर देय अतिरिक्त शुल्क में विशेष राहत प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही कृषि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पंजीकरण, कराधान, फिटनेस, बीमा एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि आरसी नवीनीकरण शुल्क में दी गई विशेष राहत 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार कृषि कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टरों के आरसी नवीनीकरण में एक वर्ष तक की देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क 500 रुपये प्रति माह की दर से लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। यदि देरी एक वर्ष से अधिक है, तब भी अधिकतम अतिरिक्त शुल्क 5,000 रुपये ही देय होगा। इसी प्रकार गैर-परिवहन श्रेणी के दोपहिया वाहनों के लिए आरसी नवीनीकरण में विलंब होने पर 300 रुपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1,000

रुपये निर्धारित की गई है। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 30 सितम्बर 2026 से पूर्व इस विशेष छूट का लाभ उठाते हुए अपने वाहनों का आरसी नवीनीकरण अवश्य करा लें। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में कृषि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग ईट, बजरी, पत्थर, रेत, खनिज, निर्माण सामग्री एवं अन्य माल के व्यावसायिक परिवहन में किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किसी भी वाहन का वर्गीकरण उसके वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जाना आवश्यक है। इसी के अनुरूप व्यावसायिक उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई कृषि ट्रैक्टर-ट्रॉली माल परिवहन, निर्माण कार्य, खनन, व्यापारिक गतिविधियों अथवा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनों में उपयोग की जाती है, तो उसका व्यावसायिक पंजीकरण अनिवार्य होगा। केवल कृषि कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियां इस व्यवस्था से मुक्त रहेंगी। व्यावसायिक उपयोग वाली प्रत्येक ट्रॉली का पृथक पंजीकरण किया जाएगा तथा उसे अलग पंजीकरण क्रमांक एवं विशिष्ट चेसिस नंबर आवंटित किया जाएगा। ऐसे वाहनों के

संचालन के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, नियमानुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा निर्धारित मोटर वाहन कर का भुगतान अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में धौलपुर, करौली, सर्वाई माधोपुर, कोटा एवं बुंदी जिलों में विशेष संयुक्त प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, खनन विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियां समन्वित रूप से कार्यवाही करेंगी। इसके बाद इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को वाहन डीलरों, निर्माताओं, व्यापारिक संगठनों, मंडी समितियों, पुलिस विभाग, खनन विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इन दोनों निर्णयों से एक ओर किसानों एवं आम वाहन स्वामियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के व्यावसायिक संचालन में पारदर्शिता आएगी, अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर नियंत्रण स्थापित होगा, सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित होगी।